दैनिक जागरण
संकल्प से ही लक्ष्य संभव होता है

देश का बही-खाता

बही-खाते के रूप में आया आम बजट अगर इस अनुमान के अनुकूल नहीं कि प्रबल बहुमत से सत्ता में लौटी मोदी सरकार बड़े आर्थिक सुधारों की राह पर अवश्य आगे बढ़ेगी तो इसके पीछे ऐसे ठोस कारण हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। सबसे बड़ा कारण देश-दुनिया के आर्थिक हालात हैं। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की चपेट में है तो विश्व अर्थव्यवस्था उथल-पुथल से ग्रस्त होने के साथ ही संरक्षणवाद से भी दो-चार है। चूंकि मौजूदा आर्थिक परिदृश्य मोदी सरकार को जोखिम लेने की इजाजत नहीं दे रहा था इसलिए उसने उससे बचते हुए आर्थिक सुधारों के साथ ही जरूरी सामाजिक सुधारों को गति देने की भरसक कोशिश की है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश आम बजट के प्रावधान यह रेखांकित कर रहे हैं कि मोदी सरकार इस वित्तीय वर्ष के साथ-साथ अपने शेष कार्यकाल के लिए भी एक खाका पेश करना चाह रही थी। शायद इसीलिए बुनियादी ढांचे में अगले पांच साल में सौ लाख करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा प्रकट किया गया है। यह एक बड़ी राशि है। इससे यह पता चलता है कि सरकार छलांग भी लगाना चाहती है और साथ ही अगले पांच वर्षों में देश को पांच लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था भी बनाना चाहती है। यह एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन देश की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए यह समय की मांग थी कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ बड़े लक्ष्य तय किए जाएं।

देश को पांच लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सालाना आठ प्रतिशत विकास दर की दरकार होगी। यह समय बताएगा कि मोदी सरकार विकास दर के इस आंकड़े को हासिल कर पाएगी या नहीं, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि आम बजट के जरिये देश के समग्र विकास की चिंता करते हुए कुछ बुनियादी समस्याओं के समाधान का भी संकल्प लिया गया है। यह अच्छा है कि हर घर को बिजली पहुंचाने और हर गांव को सड़क से जोड़ने के साथ जल संकट को दूर करने की चिंता सरकार की प्राथमिकता में है। चूंकि जल संकट दूर करने के अभियान को सफल बनाने के अलावा और कोई उपाय नहीं इसलिए यह ध्यान रखना होगा कि इसमें जितनी जरूरत जन भागीदारी की है उतनी ही सरकारी तंत्र के सहयोग की भी। इसी क्रम में सरकार और साथ ही उसकी मशीनरी को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित खर्च के लिए वांछित धन की प्राप्ति वास्तव में हो। यह राहतकारी है कि आम बजट के माध्यम से सरकार ने यह प्रदर्शित किया कि उसे अपने इस लक्ष्य का स्मरण है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, लेकिन उसे यह पता होना चाहिए कि इस लक्ष्य को पाने का समय करीब आ रहा है। आम बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने भी यह उम्मीद जताई कि बजटीय प्रावधान उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के साथ कारोबार जगत को गति प्रदान करेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वास्तव में ऐसा हो। निःसंदेह ऐसा तभी होगा जब कारोबार जगत के अनुकूल माहौल का निर्माण भी हो सकेगा।

बंगाल बिजनेस समिट

पिछले आठ वर्षों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निवेशकों को बंगाल की ओर आकर्षित करने का प्रयास करती आ रही हैं। विदेशों में निवेशकों से मिलने के साथ-साथ बंगाल में भी कई बार उद्योग सम्मेलन आयोजित कर चुकी हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। 2015 से ममता सरकार राज्य में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट आयोजित करती आ रही हैं। बड़े पैमाने पर हर वर्ष इस उद्योग सम्मेलन को आयोजित किया जाता है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि आगे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हर दो साल पर होगा। बिजनेस समिट का पांचवां संस्करण इस साल फरवरी में हुआ था। ममता ने विधानसभा में कहा-'हर साल राज्य सरकार बड़े निवेश प्रस्तावों का एलान करती है। महत्वपूर्ण यह है कि नए प्रस्तावों की दिशा में कदम उठाने से पहले इन प्रस्तावों पर आगे बढ़ा जाए और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। अब से हम बिजनेस समिट को हर दो साल में आयोजित करेंगे।' उन्होंने बाद में कहा कि अगला बीजीबीएस 2021 में आयोजित होगा। यहां बताना आवश्यक है कि 2021 में आगामी विधानसभा चुनाव भी होना है। पिछले तीन बिजनेस समिट में केंद्र सरकार की ओर से एक भी मंत्री नहीं पहुंचा। हालांकि देश-विदेश के बड़े उद्योगपति एवं उनके प्रतिनिधिदल जुटते थे। हर वर्ष दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आने का दावा किया जाता रहा, लेकिन देखा जा रहा है कि बड़े उद्योग बंगाल में अब तक नहीं लग पाए हैं। ऐसे में इस उद्योग सम्मेलन को लेकर विपक्षी पार्टियां-माकपा, कांग्रेस से लेकर भाजपा तक यह सवाल करने लगी हैं कि करोड़ों रुपये खर्च कर इतने तामझाम के साथ उद्योग सम्मेलन करने का नतीजा क्या निकल रहा है? वहीं ममता बनर्जी भी शायद मानने लगी हैं कि हर वर्ष सम्मेलन करने से उद्योगपतियों के बीच भी आकर्षण कम हो जाता है। जितने निवेश प्रस्ताव आए हैं, वे सभी क्रियान्वित हो जाएं तो भी स्थिति बेहतर हो जाएगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री पूरी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोले हुई हैं। वहीं भाजपा भी बंगाल में 18 सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दे चुकी है।

सतत विकास के लिए प्रयास

धर्मकीर्ति जोशी

मौजूदा मुश्किलों का हल निकालने के लिए बजट में कुछ कदम उठाने की कोशिश हुई है ताकि वृद्धि को रफ्तार दी जा सके। इसके लिए ज्यादा जोखिम नहीं लिया गया

पूरी दुनिया के साथ भारत भी इस वक्त आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट इसी अनिश्चितता के दौर में पेश हुआ। पांच महीने पहले पेश अंतरिम बजट से लेकर मौजूदा माहौल में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। इसकी वजह भी स्पष्ट है। हालात इतनी जल्दी नहीं बदलते। जुलाई 2014 के पूर्ण बजट में मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था में मंदी के बाद भी संप्रग सरकार के अंतरिम बजट के राजकोषीय लक्ष्यों को हासिल किया था। मोदी सरकार अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद 2014 की तरह इस बार भी इस मोर्चे पर कामयाब रही। हालांकि अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की जरूरत फरवरी में आए अंतरिम बजट की तुलना में अब और ज्यादा बढ़ गई है। वित्त मंत्री के समक्ष प्रश्न यह नहीं था कि क्या वृद्धि को तेजी देने के लिए राजकोषीय अनुशासन से समझौता किया जाए, बल्कि यह था कि वृद्धि में आ रही गिरावट को देखते हुए क्या राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम यानी एफआरबीएम एक्ट में जताई गई प्रतिबद्धता के लिहाज से कोई छूट ली जा सकती है या नहीं? सरकार ने वित्त वर्ष 2019 में वित्त वर्ष 2020 के लिए राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य तय किया था उसे अंतरिम बजट में 20 आधार अंक बढ़ा दिया। बहरहाल केंद्र और राज्यों का जीडीपी के अनुपात में कर्ज का मिश्रित आंकड़ा भारत के बराबर रेटिंग वाले देशों में काफी ऊंचा है। ऐसे में राजकोषीय घाटे में जरा भी कटौती की कोई गुंजाइश नहीं थी।

सरकार ने समझदारी के साथ इस मोह को छोड़ते हुए राजकोषीय अनुशासन के मोर्चे पर अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूती से जाहिर किया। इसके तहत चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी का 3.3 प्रतिशत कर दिया जो पहले 3.4 प्रतिशत तय किया था। निवेश, निजी उपभोग और निर्यात में सुस्ती स्पष्ट है। इसके चलते वित्त वर्ष 2019 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर सिकुड़कर 6.8 प्रतिशत रह गई जो वृद्धि का पांच साल में सबसे न्यूनतम स्तर है। जीडीपी के अनुपात में घरेलू बचत घटी है। इससे सरकारी घाटे की भरपाई और निजी निवेश के लिए उपलब्ध बचत कोष का आकार भी घटा है। वहीं कर्ज की सूखी धारा में नई जान डालने के लिए सरकारी बैंकों के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि वे एनपीए के बढ़ते बोझ से त्रस्त हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी में उनके काफी संसाधन फंसे हुए हैं।

इस लिहाज से मौजूदा मुश्किलों का हल निकालने के लिए बजट में कुछ समाधान निकालने का प्रयास हुआ है जिनसे वृद्धि को रफ्तार दी जा सके। अच्छी बात यह है कि इसके लिए ज्यादा जोखिम नहीं लिया गया और मध्यम अवधि की रणनीतिक चुनौतियों की अनदेखी नहीं की गई। रियल एस्टेट और एनबीएफसी को मिलने वाली मदद से कुछ मुश्किलें जरूर हल होंगी। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से भी कर्ज देने की उनकी क्षमता में सुधार होगा। यदि वृद्धि की रफ्तार सुस्त होती है तब चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का 3.3 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने कर संग्रह में 9.5 प्रतिशत का मामूली वृद्धि का ही अनुमान व्यक्त किया है जो कि बजट में 12 प्रतिशत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि की दर से कम है। ऐसे में विनिवेश से लेकर सरकारी परिसंपत्तियों को सही तरह से भुनाने की दरकार होगी। ऐसा करते हुए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पूंजीगत व्यय से कोई समझौता न किया जाए।

बजट में राजकोषीय संयम का पहला संदेश तो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए है कि वह मौद्रिक नीति में कुछ नरमी कर सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि राजकोषीय नीति ही मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णायक आधार होती है। वर्ष 2019 में रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में अभी तक 75 आधार अंकों की कटौती की है और हम अगली समीक्षा में एक और कटौती की उम्मीद कर सकते हैं। कमतर राजकोषीय घाटा सरकारी बांडों के लिए भी शुभ संकेत हैं जो पिछले कुछ समय से रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कटौती, कच्चे तेल की कीमतों में कमी और विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों की नरम नीतियों से दबाव का सामना कर रहे हैं।

बजट और मौद्रिक नीति से निजी उपभोग को कुछ सहारा मिलेगा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से वृद्धि की रफ्तार जोर पकड़ेगी, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती तब अपना असर दिखाएगी। न्यूनतम आय समर्थन से किसानों और कर रियायतों से मध्य वर्ग के हाथ में जो पैसा पहुंचेगा उससे उपभोग मांग में इजाफा होगा, क्योंकि इस तबके में उच्च वर्ग की तुलना में मांग को प्रभावित करने की क्षमता कहीं अधिक है। बहरहाल चालू वित्त वर्ष में वृद्धि की चाल कुछ हद तक बजट के नियंत्रण से बाहर है। वास्तव में मानसून और कच्चे तेल की कीमतों का रुख भी इसमें अहम भूमिका निभाएगा।

अगर इस बार लगातार चौथे साल मानसून सामान्य के बराबर रहता है और कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा दरों के दायरे में रहती हैं तो भारत की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। वहीं अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य और अपर्याप्त वर्षा के चलते वृद्धि में गिरावट की आशंका बढ़ सकती है। जून में वर्षा सामान्य से 36 प्रतिशत कम रही, लेकिन फसल उत्पादन के लिए जुलाई-अगस्त की वर्षा और उसका समान वितरण कहीं अधिक मायने रखता है। यदि ऐसा हुआ और खाद्य उत्पादों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी किसानों की जेब में पहुंचती है तब ग्रामीण मांग में सुधार समग्र अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत की वृद्धि में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो विनिर्माण में 50 प्रतिशत और सेवा में एक चौथाई हिस्से को प्रभावित करती है।

इसके अलावा कुछ नीतिगत कदम भी निवेशकों के भरोसे को बढ़ा सकते हैं जिससे वृद्धि को सहारा मिलेगा। इसके लिए बजट में बुनियादी ढांचे पर एकदम सही तरह से ध्यान दिया गया है। विनिर्माण में निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की गई है और इसके लिए आवंटन का दायरा बढ़ाने के बजाय कर प्रोत्साहन के जरिये आकर्षक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की कवायद की गई है। इससे विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी और वे उत्पादन इकाइयां भी भारत का रुख कर सकती हैं जो अमेरिका-चीन की तनातनी के बाद चीन से बाहर निकलने की जुगत कर रही हैं।

राजस्व जुटाने के लिए सरकार ने करों पर ज्यादा दांव नहीं लगाया है। वह विनिवेश और अपनी अन्य परिसंपत्तियों पर अधिक भरोसा कर रही है। सरकार को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल को भी नए सिरे से पेश करने की दरकार है जिसमें दोनों पक्षों के लिए जोखिम साझेदारी संतुलित हो। अर्थव्यवस्था की तेज और सतत वृद्धि के लिए निजी निवेश को पटरी पर लाना बेहद आवश्यक है।

(लेखक क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

कम कमाई और ज्यादा खर्च का संकट

विवेक कौल

असली विनिवेश तो तब होगा जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी कंपनियों को बेचेगी

देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश करते हुए जो लेखा-जोखा सामने रखा उसके अनुसार सरकार 2019-20 में 27.86 लाख करोड़ रुपये खर्च करना चाहती है, लेकिन इस साल सरकार की कुल कमाई 20.82 लाख करोड़ रुपये रहने की ही उम्मीद है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का राजकोषीय घाटा करीब 7.04 लाख करोड़ रुपये यानी सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत रहेगा। सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर ही राजकोषीय घाटा है। ऊपरी तौर पर देखें तो 3.3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा सीमित दिखाई देता है, लेकिन जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं, द डेविल इज इन द डिटेल तो इस वर्ष सरकार जितना टैक्स जुटाना चाहती है उससे यही लगता है कि वह कुछ ज्यादा ही आशान्वित है। इस साल सरकार आयकर से 5.69 लाख करोड़ रुपये जुटाने की आशा रखती है। यह पिछले वित्त वर्ष से 23.3 प्रतिशत अधिक है। सरकार इस साल तीन लाख करोड़ रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुटाने की उम्मीद कर रही है। यह भी पिछले साल से करीब 30 फीसद अधिक है। सीमा शुल्क से 1,55,904 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद की गई है, लेकिन यह बीते बरस से करीब 32.2 फीसद ज्यादा है। सरकार को कंपनी कर और जीएसटी में करीब 15 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है। इस उम्मीद के बीच इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि इस वित्त वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रही है। अगर कारों, दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों की बिक्री जैसे संकेतकों को देखें तो लगता है कि अर्थव्यवस्था पिछले साल से और भी ज्यादा कमजोर पड़ गई है। ऐसे में इन करों में सरकार के मन मुताबिक वृद्धि काफी मुश्किल लगती है।

सरकार इस साल विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ जुटाएगी। यह पिछले साल से करीब 31.3 फीसद अधिक है। देखना यह है कि सरकार असल विनिवेश करती है या फिर एक सरकारी कंपनी को दूसरी सरकारी कंपनी को बेचती है? जनवरी 2018 में ओएनजीसी ने एचपीसीएल को 36,915 करोड़ रुपये देकर खरीदा। इसके लिए कंपनी को करीब 25,000 करोड़ रुपये उधार लेना पड़ा था। ऐसे विनिवेश का कोई अर्थ नहीं। असली विनिवेश तब होगा जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी कंपनियों को बेचेगी, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा होता नहीं दिखता। इसके बावजूद विनिवेश की प्रक्रिया में एक अच्छी चीज यह हुई है कि सरकार ने राष्ट्रीय निवेश कोष बनाने की बात की है। विनिवेश से जो पैसा आएगा वह इस कोष में जाएगा और उसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों पर खर्च करने के अलावा रेलवे में पूंजीगत व्यय के निवेश के लिए किया जाएगा।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में 51 फीसद हिस्सेदारी की मौजूदा नीति को बदला जाएगा। अगर सरकार सही मायने में अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचती है तो यह एक अच्छा कदम होगा, लेकिन यदि इस बदलाव का इस्तेमाल भारतीय जीवन बीमा निगम को अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए करती है तो यह इस बदलाव का गलत इस्तेमाल होगा। जो भी हो, यह अच्छी बात है कि वित्त मंत्री ने श्रम कानून में सुधार की पहल की। यह जरूरी था। अपने यहां केंद्रीय सरकार के स्तर पर करीब 44 श्रम कानून हैं। अगर राज्यों के स्तर के श्रम कानूनों को गिना जाए तो करीब 200 श्रम कानून और हैं। इतने सारे श्रम कानून होने से कारोबारी एक स्तर के बाद और बड़े होने की कोशिश छोड़ देते है। यही वजह है कि विनिर्माण कंपनियों में या तो 50 से कम लोग होते हैं या फिर 200 से अधिक। मोदी सरकार यह चाह रही है कि केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम कोड के एक सेट में डाल दिया जाए। यह एक अच्छा प्रस्ताव है, पर देखना यही है कि ऐसा हो पाता है या नहीं? ध्यान रहे कि 2015 में भी मोदी सरकार ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मजदूर संगठनों के दबाव में आगे नहीं बढ़ पाई। देश में रोजगार पैदा करने के लिए श्रम सुधार जरूरी हैं। किसी भी देश में रोजगार तब पैदा होते हैं जब लघु उद्योग बड़े होते हैं।

सरकार ने इस साल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश का निर्णय लिया है। पिछले दो सालों में सरकार इन बैंकों में करीब 2.06 लाख करोड़ रुपये डाल चुकी है। आखिर सरकार कब तक इन बैंकों में करदाताओं की कमाई डालती रहेगी? जरूरत तो यह है कि इन बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी 50 फीसद से कम करने को तैयार हो। इससे बैंक बाजार से पैसा उठा सकेंगे और करदाताओं का पैसा अधिक अहम कार्यों में लगाया जा सकेगा। वित्तमंत्री के पास अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार लाने का अच्छा मौका था जो उन्होंने लगभग गंवा दिया।

(इजी मनी ट्राइलॉजी के लेखक अर्थशास्त्री एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

देश का विदेशी मुद्रा भंडार

(अरब डॉलर में)
(मार्च अंत तक)

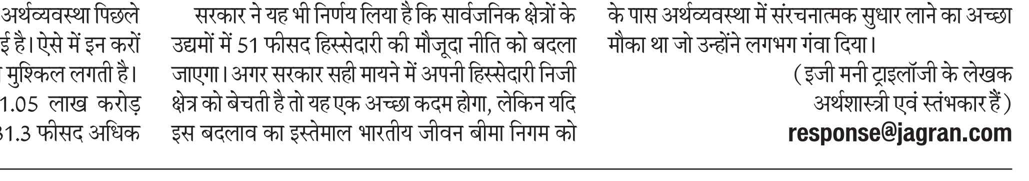

ऊर्जा

मौनव्रत

मनुष्य के ज्ञान, स्वभाव का स्तर उसकी वाणी से पता चलता है। वाणी अपनी मिठास, तर्क, क्षमता एवं भाव संवेदना से दूसरों को प्रभावित नहीं करती, अपितु प्रतिकूल स्थिति को भी अनुकूल बना लेती है। कुशल वक्ता जनमानस को बदलते हैं और उसे अपने विचारों के अनुकूल धारा में बहा ले जाते हैं। लोक व्यवहार में सफलता-असफलता का बहुत कुछ आधार उसके भाषण-संभाषण स्तर के साथ जुड़ा रहता है। अध्यात्म में वाक् सिद्धि का प्रयोजन मौन व्रत का अभ्यास करने से बनता है। निरंतर बोलने से वाणी की क्षमता क्षीण होती है। अतएव विद्वतजन निरर्थक नहीं बोलते। सोच समझकर सीमित और अर्थपूर्ण शब्द कहते हैं। उनका थोड़ा सा भी बोलना घंटों बकवास करने की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। मौन के विश्रामकाल में इतना अवसर मिल जाता है कि पिछली गंदी आदतों को सुधारा-विचारा जा सके। मौन व्रत के द्वारा भावी कार्यकाल को सुगम बनाया जा सकता है।

मौनकाल में विचारों की शक्ति सीमाबद्ध होती है। इसे इधर-उधर बिखेरने की अपेक्षा यदि वाक् शक्ति पर धार धरने में लगाया जा सके तो वह तीखी तलवार से भी अधिक सशक्त बनती है। मौन की पृष्ठभूमि में जप साधन ठीक प्रकार बन पड़ता है। ध्यान के लिए मौन व्रत अनिवार्य है। किसी दशा-विशेष में प्राणशक्ति को नियोजित करने का अभ्यास करना हो तो उसका प्रथम चरण मौनव्रत ही हो सकता है। बांध खोलने पर जल का प्रचंड प्रवाह उछाल मारता है, यदि उसे सामान्य गति से बहने दिया जाए तो जल धारा सामान्य स्तर की ही बनकर रह जाती है।

विचार के उपरांत वाणी का स्थान है। विचार सूक्ष्म हैं। मौन व्रत से उपासना की शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है और उस आधार पर निग्रहित की गई जिह्वा (जीभ) जो कुछ कहती है, वह शुभ सत्य होकर रहता है। जिह्वा के कार्यक्षेत्र लौकिक भी हैं और पारलौकिक भी। लोक व्यवहार में यह सबसे बड़ी क्षमता है। अध्यात्म में सत्संग, विचार-विनिमय जिह्वा से ही संपन्न होते हैं। वाणी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मौन व्रत का ही अवलंबन लेना चाहिए। सप्ताह में एक दिन या दिन में दो-तीन घंटे का मौन व्रत रखना जीवन के लिए बहुत उपयोगी है।

श्रीमती रमन त्रिपाठी

लाल कपड़े में लिपटा 'स्वदेशी बजट'!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब दो घंटे का बजट भाषण दिया, लेकिन यह आम बजट संसद में पेश होने से पहले ही चर्चा में आ गया। वजह-उस ब्रीफकेस का नदारद रहना जिसे वर्षों से सभी सरकारों के वित्त मंत्री बजट के दिन दिखाते नजर आते थे। जब कभी बात बजट की होती है तो दिमाग में एक लाल रंग का ब्रीफकेस घूमने लगता है। यह वही ब्रीफकेस होता है, जो बजट वाले दिन वित्त मंत्री के हाथों में होता है और जिसमें बजट होता है, लेकिन इस बार उसकी जगह ले ली लाल मखमली कपड़े में लिपटे बजट पेपर्स ने। इसे 'बही खाता' नाम दिया गया है। आजादी के बाद आज तक हमेशा बजट ब्रीफकेस में ही दिखा, लेकिन इस बार बजट को स्वदेशी बनाते हुए उसे पारंपरिक तरीके से लाया गया है। ठीक वैसे, जैसे बेहद पूज्यनीय ग्रंथों को लाया जाता है।

वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा-यह भारतीय परंपरा है और यह पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है। यह बजट नहीं, बहीखाता है। मोदी सरकार हमेशा से ही स्वदेशी होने की बात कहती है और अब उसे बजट में भी लागू कर दिया गया है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कई बदलाव किए गए, जिससे अंग्रेजी तरीके से बजट पेश करने के तरीके बदले गए।

फिर से

सत्ता में आने के बाज आम बजट से जुड़े कई बदलाव मोदी सरकार कर चुकी है और अब बारी है वित्त वर्ष को बदलने की

बजट की तारीख को 28 फरवरी से बदल कर 2017 में 1 फरवरी कर दिया गया। 2000 तक बजट 5 बजे पेश होता था, लेकिन 2001 में वाजपेयी सरकार ने इस परंपरा को बदला। बजट पेश करने का वक्त शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे किया। पहले रेल बजट और आम बजट अलग-अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में इन दोनों को एक में जोड़ दिया गया। अब 2019 में बजट में दिखने वाला ब्रीफकेस भी बदल गया है और उसकी जगह लाल कपड़े में लिपटे बही खाते ने ले ली है। सीतारमण के हाथ में लाल कपड़े में लिपटा बजट देखकर हर कोई थोड़ा हैरान भी था। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह भारतीय परंपरा के अनुसार है। यह दिखाता है कि हम पश्चिमी गुलामी से बाहर निकल रहे हैं। यह कोई बजट नहीं है, बल्कि बही खाता है। कुछ इसे अच्छा बदलाव बता रहे हैं। इसी बीच पत्रकार रशीद किदवई ने सवाल उठाया है कि वित्त मंत्री का ब्रीफकेस कहा हैं? वित्त मंत्रालय की एक और परंपरा खत्म हो गई? इस पर एक अन्य पत्रकार सुमित अवस्थी ने भी सवाल किया है कि आखिर आप ब्रीफकेस क्यों देखना चाहते हैं? बही खाते में गलत क्या है?

अब बारी वित्त वर्ष बदलने की : बजट से जुड़े कई बदलाव मोदी सरकार कर चुकी है और अब बारी है वित्त वर्ष को बदलने की। अभी तक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, जबकि साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। अब मोदी सरकार धीरे-धीरे वित्त वर्ष की अवधि भी बदल कर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करेगी। वैसे भी मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल से ही इस पर विचार हो रहा है और उम्मीद है कि इस कार्यकाल में सरकार यह फैसला भी ले लेगी। वैसे भी, इतने तगड़े जनादेश वाली भाजपा के लिए यह बदलाव करने का इससे अच्छा मौका शायद ही कोई और होगा।

(साभार : आइचौक.इन में अनुज मौर्या)

शिक्षक की भूमिका

बेहतर शिक्षक ही कर सकेंगे कायाकल्प शीर्षक से लिखे अपने लेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने भारत के भविष्य निर्माण में शिक्षक की भूमिका को अहम माना है। निःसंदेह आज देश यदि प्रगति के पथ पर है तो उसमें शिक्षकों के योगदान और समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता। शिक्षा एक ऐसा मापदंड है जिससे किसी देश की प्रगति को मापा जा सकता है। शिक्षा को बेहतर करने की परिकल्पना बगैर शिक्षक के तो की ही नहीं जा सकती। शिक्षक को यदि गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए तो निश्चय ही शिक्षक अपना शत प्रतिशत योगदान शिक्षा के स्तर को उठाने में लगाएगा। प्रतिभावान छात्र को उसके छात्र जीवन से ही शिक्षक बनने की प्रेरणा दी जाए तो बेहतर परिणाम निकल सकते हैं। नई शिक्षा नीति में 2022 तक पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी और शिक्षा मित्र को बंद करने का प्रस्ताव साहसिक जरूर हो सकता है, लेकिन मानवीय नहीं होगा। इसलिए उन्हें हटाने के बजाय शिक्षा का अंग बनाए रखना एवं उनके जीवकोपार्जन के लिए आर्थिक संरक्षण प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है।

सर्वजीत आर्या, प्रधानाचार्य, कन्नौज

शहरों में पानी की बर्बादी

जब भी हम अपने घरों में आरओ फिल्टर मशीन चलाते हैं, तो एक लीटर पानी प्राप्त करने के लिए 3 लीटर अच्छी गुणवत्ता वाला पानी बर्बाद करते हैं। 10 लोगों के एक परिवार को अगर 1 दिन में 100 लीटर शुद्ध पेयजल की आवश्यकता हो सकती है तो हर दिन फिल्टर की प्रक्रिया में ढाई सौ लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के अधिकांश मध्यवर्गीय परिवार आरओ मशीन का उपयोग करते हैं। ऐसे में प्रतिदिन करोड़ों लीटर पानी बेकार हो जाता है। जहां एक तरफ आरओ मशीन पानी को स्वच्छ करने का साधन बना, तो दूसरी तरफ पानी को बर्बाद करने का जरिया भी बना। भूजल के घटते स्तर का दोष किसानों पर थोप दिया जा रहा है। ट्यूबवेल के चलने और धान के खेतों में पानी भरे होने के साथ अनुमान लगाया जाता है कि खेतों में उपलब्ध पानी का 70 फीसद खर्च होता है। एक अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक 8 मिनट में शावर में 65 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। एक आदमी औसतन 15 से 20 मिनट शावर का इस्तेमाल करता है। पानी बचाने के लिए ऐसी आदतें बदलने की आवश्यकता है।

durgesh040796@gmail.com

मेलबाक्स

सभी धर्मों का सम्मान

पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से सांसद नुसरत जहां ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं। नुसरत जहां अपनी बेबाकी व सटीक बोलने के लिए चर्चित हैं। आज हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है वह है सभी धर्मों का सम्मान करने की, लेकिन हम आज भी एक दूसरे के धर्म का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नुसरत जहां जैसी सांसद को एक आदर्श मार्गदर्शिका बनकर लोगों में अलख जगाना होगा कि हम सब धर्म व जाति से बाद में हैं, सबसे पहले मानव हैं व मानव बनकर एक दूसरे का सम्मान करें। यही इंसानियत है व इसी में हम सब का कल्याण है।

hemahariupadhyay@gmail.com

मुंबई की बारिश

मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इसके साथ ही मुंबई नगर निगम देश की सबसे अमीर नगर पालिका है। इसका सालाना बजट लगभग 800 करोड़ का है। देश में जितना भी टैक्स आता है, उसमें से 32 प्रतिशत मुंबई के लोग ही देते हैं, लेकिन पहली बरसात ने ही मुंबई की गति को रोक दिया है। बीएमसी और वहां की स्थानीय सरकार पूरी तरह फेल नजर आती है। मुंबई में हर साल इस तरह की बारिश होती है और यही नजारा रहता है। जनता इसे झेलने को विवश रहती है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

हम भी रहें सतर्क

दुर्घटना लापरवाही के कारण ही होती है। इसके बावजूद हम अपनी गलती ना मानते हुए दूसरे पर ही आरोप लगाते रहते हैं। सरकार को कोसते हैं, प्रशासन को नकारा बताते हैं। परंतु हकीकत यह है कि हम आपराधिक घटनाओं के बाद भी सतर्क नहीं रहते और हमारी यही लापरवाही दुर्घटनाओं और अपराधों को बढ़ावा देती है। सरकार और प्रशासन तो अपना काम करता है और करेगा भी। परंतु हमें भी सतर्क और जागरूक रहकर अपने देश शहर, घर और परिवार को सुरक्षित रखना होगा।

एकता, डा. भीम राव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली विवि

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।